

(Gujarat), Shri Dorjee Tshering Lepcha (Sikkim), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Shri S. Selvaganabathy (Puducherry), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra).

Concern over the rising use of narcotic drugs among adolescents and young adults

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Thank you, Sir, for the opportunity. This is a grave concern of the State of Kerala. The adolescents, young boys and girls are dripping into the drugs at a very high level. I wish to draw your attention towards the three instances which have actually shocked the entire conscience of Kerala people. One was an instance that happened on the New Year's eve in which a fourteen-year old boy killed a thirty-year old man when he was questioned on using drugs in public place. The police also confirmed that the weapon belonged to the minor, which shows how deep the drugs have infiltrated into our society. The second instance was from Malappuram where a son killed his own mother under the influence of drugs. And when police arrested him, the boy smiled at the police. That is the kind of effect the drugs have on the youth. In the third instance, a boy killed three members of a family from neighbourhood, again under the influence of drugs. Sir, escalation in drug-related crimes in Kerala is deeply concerning. The number of cases under the narcotic drugs and psychotropic substances surged from 5,695 in 2021 to 26,619 in 2022, a nearly five-fold increase. In 2022 alone, Kerala accounted for 27,545 drug-related arrests, representing 29.4 per cent of India's total NDPS arrests. Recent data from the Kerala Police Department indicates that Ernakulam District alone recorded 8,567 narcotic cases from January 1st, 2023 to June 1st 2024, the highest in the State. Overall, 41,531 cases were registered under the NDPS Act in the same period. The NCB has further confirmed that high intensity drugs like MDMA, LSD and cocaine are being trafficked into Kerala from international sources, worsening the crisis.

A survey of the Kerala Excise Department indicates a sharp rise in drug demand among adolescents, further exposing the failure to control this menace. The Azad India Foundation's 2019 report highlighted the nationwide increase in drug addiction, with a UN Report estimating one million registered heroin addicts in India, while unofficial figures suggest over five million. Given the gravity of the situation in Kerala, I urge the Union Government to collaborate with the State in formulating a comprehensive national strategy to combat drug addiction.

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) : माननीय सदस्य, समय समाप्त हुआ। The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Shrimati

Jebi Mather Hisham : Shri Haris Beeran (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Sujeet Kumar (Odisha) and Shri Sanjeev Arora (Punjab). श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल।

Demand to address the problems faced by farmers in Maharashtra

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र): * “सभापति जी, मुझे आज का विषय मराठी में रखने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं कृषि सम्बन्धी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ। प्रकृति के प्रकोप और प्रशासन की उदासीनता से सबसे अधिक पीड़ित किसान ही हैं। देश के अन्नदाता के रूप में इन किसानों की प्रशंसा करते हुए भी, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किया जा रहा है। भारत में, विशेषकर महाराष्ट्र में, यदि कोई सबसे कठिन परिस्थिति में है, तो वह किसान हैं। ये सत्य है कि विशेषकर मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र के किसान फसल नष्ट होने और कर्ज के बोझ जैसी समस्याओं के कारण आज मौत का सामना कर रहे हैं। कल वाणिज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि महाराष्ट्र के किसानों का 7.38 लाख रुपया बकाया है।

2021 में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि वह एक रुपये में कृषि बीमा दिलाएगी। किसानों ने इस उम्मीद के साथ बीमा कराया था कि अगर उनकी फसलें बर्बाद भी हो गईं तो भी उन्हें बीमा कवरेज मिलेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ, बल्कि महाराष्ट्र में करीब-करीब 500 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा बीमा घोटाला हुआ है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ, यह आरोप सत्तारूढ़ भाजपा विधायक ने लगाया है। सोयाबीन, कपास, प्याज समेत कई फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को लेकर किए गए वादे कब पूरे होंगे, इस सवाल पर भी सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस साल सोयाबीन की फसल तैयार है, लेकिन सोयाबीन रखने के लिए जूट की थैली नहीं होने के कारण इसकी खरीद नहीं हो रही है। सोयाबीन खरीद के लिये समय सीमा आठ दिन बढ़ाने के बाद भी किसान सोयाबीन बेचने के लिए रात रात भर लाइन में लगे रहे। लेकिन कुछ स्थानीय लोग पहले से ही सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। सोयाबीन का अनुमानित मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसान को बमुश्किल 3.8-4.5 हजार रुपये ही मिल रहे हैं। एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की मांग भी लंबित है। कई किसानों ने एक साल पहले से महा-डीपीटी पोर्टल पर ड्रिप सिंचाई के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है। इसके लिए आवश्यक राशि का भुगतान किए जाने के एक वर्ष बाद भी, इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है। कम से कम महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है।

मेरे राज्य में चूंकि कृषि के लिए रात में बिजली की आपूर्ति की जाती है, इसलिए किसानों को अपनी फसलों को पानी देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। किसानों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना चाहिए। कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है। उर्वरकों, कीटनाशकों,

* Hindi translation of the original speech delivered in Marathi.